खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में किया जाएगा 132 करोड़ रुपये का निवेश

राज्य, जागरण ● लखनऊ: प्रदेश में जल्द 132 करोड़ रुपये के निवेश से खाद्य प्रसंस्करण की 17 परियोजनाएं शुरू होंगीं। उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत खाद्य प्रसंस्करण के नवीन प्रस्तावों के परीक्षण के लिए बनी अप्रेजल समिति ने इन प्रस्तावों को राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी (एसएलईसी) के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति कर दी है। वहीं वाराणसी के निवेशक द्वारा 34 हजार किलोग्राम बिस्कुट दुबई निर्यात किए जाने संबंधी प्रस्ताव की भी निर्यात प्रोत्साहन सब्सिडी श्रेणी के तहत संस्तुति की गई है।

शनिवार को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीना की अध्यक्षता में अप्रेजल समिति की बैठक में सदस्यों व प्री-अप्रेजल समिति द्वारा संस्तुत की गई परियोजनाओं से संबंधित सहारनपुर, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ, अमरोहा, शाहजहांपुर, मथुरा, सीतापुर, अलीगढ़, झांसी, बदायूं, पीलीभीत, कुशीनगर, वाराणसी एवं बुलंदशहर के निवेशकों ने प्रतिभाग किया। सोलर पावर प्लांट, बेकरी, पल्प, फ्रूट जूस, फ्रोजन फूड, नमकीन, पीनट्स, पशु आहार, लालीपाप, जैली, कैंडी आदि से संबंधित 23 प्रस्ताव समिति के सामने प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 17 की संस्तुति की गई।

17 परियोजनाएं एसएलईसी को भेजीं अप्रेजल समिति ने

बैठक में पूर्वांचल क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त न होने पर चिंता जताई गई। अधिकारियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के व्यापक प्रचार-प्रसार करने और पूर्वांचल में अधिक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये गये। बीएल मीणा ने बताया कि नीति के तहत अब तक 332 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, इनमें से 50 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।